भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 80

20.07.2026 को उत्तर के लिए

लाइफ आंदोलन और जलवायु कार्य संबंधी पहलें

80. श्री अनन्त नायकः
श्री लुम्बाराम चौधरीः
श्री विजय कुमार दूबेः
श्री नलिन सोरेनः
डॉ. निशिकान्त दुबेः
श्री राजीव प्रताप रूडीः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पर्यावरण के लिए जीवन शैली (लाइफ) आंदोलन की शुरुआत के बाद से इसके तहत हुई प्रगति और इसके अंतर्गत शुरू की गई प्रमुख गतिविधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों (एनडीसी) की दिशा में प्रगति, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के विस्तार और उत्सर्जन तीव्रता में कमी सहित जलवायु संबंधी कार्य के क्षेत्र में प्रमुख उपलब्धियां क्या हैं;

(ग) क्या ओडिशा के क्योंझर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लाइफ आंदोलन या अन्य जलवायु पहलों के तहत कोई परियोजनाएं या जागरूकता कार्यक्रम लागू किए गए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी निधि आवंटित की गई है; और

(घ) ये पहलें किस प्रकार एक विकसित राष्ट्र बनने और वर्ष 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने के उद्देश्य में योगदान दे रही हैं?

उत्तर

पर्यावरण,वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ग) मिशन लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवनशैली) का उद्देश्य व्यक्तियों और समुदायों को एक ऐसी जीवनशैली का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करना है जो प्रकृति के साथ तालमेल बिठाती है, जिसमें संपूर्ण-सरकार और संपूर्ण-समाज के दृष्टिकोण के माध्यम से सात विषयों अर्थात् ऊर्जा बचाएं, पानी बचाएं, अपशिष्ट कम करें, ई- अपशिष्ट कम करें, एकल उपयोग प्लास्टिक को ना कहें, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और संधारणीय खाद्य प्रणालियों को अपनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अक्टूबर 2022 में 'मिशन लाइफ ' की शुरुआत के बाद से इसके तहत किए गए मुख्य कार्यकलापों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- मिशन लाइफ के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए "एक राष्ट्र एक मिशन: प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करें", "हरित योग" (अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की पूर्व संध्या पर), स्वच्छता ही सेवा अभियान, विश्व पर्यावरण दिवस पूर्व अभियान आदि जैसे राष्ट्रव्यापी जन-जागरण अभियान चलाए गए हैं। एक प्रमुख अभियान "एक पेड़ माँ के नाम" पहल ने सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त किया है और इसके तहत 272 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं।

- पेरिस समझौते के तहत भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) में मिशन लाइफ सिद्धांतों को जोड़ा गया।

- मंत्रालय के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के तहत, छात्र संधारणीय आदतों को बढ़ावा देने के लिए कार्यशालाओं, प्रकृति शिविरों, प्रदर्शनियों, प्रतियोगिताओं और ग्रीष्मकालीन कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। मंत्रालय के तहत पर्यावरण सूचना, जागरूकता, क्षमता निर्माण और आजीविका कार्यक्रम (ईआईएसीपी) केंद्र भी मिशन लाइफ के विभिन्न विषयों पर जनसंपर्क और क्षमता निर्माण गतिविधियों का आयोजन करते हैं।

- माई गव, पोर्टल के माध्यम से आईडियाज4लाइफ, ई-अपशिष्ट जागरूकता एवं न्यूनीकरण अभियान, तथा विभिन्न अन्य बड़े पैमाने के जागरूकता कार्यकलापों जैसे अभियानों के माध्यम से बड़ी संख्या में युवाओं को संगठित करने की पहल भी की जा रही है।

- युवाओं को व्यावहारिक ज्ञान सीखने का अनुभव प्रदान करने के लिए, युवा कार्य और खेल मंत्रालय के 'माई भारत' पोर्टल पर 'मिशन लाइफ' पर आधारित 10-दिवसीय अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया गया।

- मिशन लाइफ के लिए 12 लाख से ज़्यादा इको-क्लब स्कूलों में बच्चों और युवाओं को पर्यावरण के प्रति जागरूकता और टिकाऊ जीवनशैली को बढ़ावा देकर व्यवहार संबंधी बदलाव लाने का काम कर रहे हैं।
- मंत्रालय द्वारा दो समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रारम्भ किए गए हैं - मिशन लाइफ पोर्टल-एक ज्ञान भंडार के रूप में और मेरी लाइफ पोर्टल-लाइफ संबंधी घटनाओं और कार्यकलापों की संरचित रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए है। अब तक, देश भर में 40 लाख से अधिक लाइफ़ कार्यक्रमों में 7.3 करोड़ से अधिक लोगों ने भाग लिया है, जिसमें पिछले 2 वर्षों के दौरान ओडिशा के क्योंझर में 3428 लाइफ़ संबंधित जागरूकता और भागीदारिता कार्यक्रमों में 100279 प्रतिभागी शामिल हैं।
- मिशन लाइफ को भारत पर्व, स्वच्छ वायु दिवस, भारत जल सप्ताह, जी20 ईसीएसडब्ल्यूजी बैठकों, महा कुंभ मेला और विश्व पर्यावरण दिवस 2025 आदि जैसे प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रमों में इंटरैक्टिव डिजिटल डिस्प्ले, वर्चुअल रियलिटी अनुभव और लाइव प्रदर्शनों वाले समर्पित लाइफ मंडपों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है।
- भारत ने सतत जीवनशैली पर वैश्विक विमर्श को आगे बढ़ाने में भी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय पड़ावों के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
    - दिनांक 1 मार्च 2024 को नैरोबी, केन्या में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (यूएनईए-6) के छठे सत्र में, श्रीलंका और बोलिविया द्वारा सह-प्रायोजित "सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना" पर भारत के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अपनाया गया।
    - भारत के "आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना" संकल्प को, 30 जुलाई 2025 को जिम्बाब्वे में आयोजित रामसर पक्षों के 15वें सम्मेलन में अपनाया गया था।
    - भारत ने वर्ष 2024-26 और पुनः वर्ष 2026-28 के कार्यकाल के लिए ' संधारणीय खपत और उत्पादन पैटर्न' (10वाईएफपी) पर कार्यक्रमों के 10-वर्षीय फ्रेमवर्क के बोर्ड में भी जगह बनाई। भारत ने सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने के अपने वैश्विक एजेंडे को और मजबूत करते हुए बोर्ड में सह-अध्यक्ष की भूमिका भी ग्रहण की है।

पिछले कुछ वर्षों में, मिशन लाइफ़ सतत जीवनशैली पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है, जिसे शर्म अल-शेख कार्यान्वयन योजना (सीओपी27), जी7 कम्युनिक और जी20 नई दिल्ली नेताओं की उदघोषणा सहित प्रमुख वैश्विक मंचों

पर स्वीकार किया गया है, जो भारत के वैश्विक जलवायु नेतृत्व और मिशन की सार्वभौमिक प्रासंगिकता की पुष्टि करता है।

(ख) और (घ) भारत ने जलवायु से संबंधित कार्रवाई में महत्वपूर्ण प्रगति की है और पेरिस समझौते के तहत अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) को प्राप्त करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। विवरण नीचे दिए गए हैं:

- संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफ़सीसीसी) को सौंपी गई भारत की पहली द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट (बीटीआर-1) के अनुसार, वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में वर्ष 2022 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की उत्सर्जन तीव्रता में 37.38 प्रतिशत की कमी आई।
- वन और वृक्ष आवरण का भी लगातार विस्तार हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2005 और वर्ष 2022 के बीच 2.44 बिलियन टन सीओ2 समतुल्य का अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाया गया है।
- भारत ने वर्ष 2030 के लक्ष्य से पांच वर्ष पहले गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित ऊर्जा स्रोतों से अपनी संचयी स्थापित विद्युत ऊर्जा क्षमता का 50 प्रतिशत से अधिक पूरा करने की महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त कर ली है।
- सरकार ने भारत के स्वच्छ ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और निम्न कार्बन औद्योगिक विकास का समर्थन करने के लिए पीएम सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने, सौर फोटोवोल्टिक (पीवी) मॉड्यूल और बैटरी के घरेलू विनिर्माण और उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) जैसी कई प्रमुख पहल और योजनाएं लागू की हैं।
- सरकार उन सेक्टरों के लिए भी कार्बन कैप्चर, यूटिलाइज़ेशन और स्टोरेज (सीसीयूएस) टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रही है, जहाँ उत्सर्जन कम करना मुश्किल है।
- भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए), आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन (सीडीआरआई), वैश्विक बायोफ्यूल एलायंस और लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन (लीडआईटी) जैसी पहलों के माध्यम से वैश्विक जलवायु से संबंधित कार्रवाई को और मजबूत किया है।
- जलवायु संबंधित वित्त जुटाने और निम्न कार्बन विकास का समर्थन करने के लिए, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम आदि जैसे उपाय शुरू किए गए हैं।

- अनुकूलन के स्तर पर, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसी) और जलवायु परिवर्तन पर संरेखित राज्य कार्य योजनाएं (एसएपीसीसी), जलवायु अनुकूल जल और कृषि क्षेत्रों के लिए कार्यक्रमों, हीट एक्शन प्लान और बेहतर आपदा पूर्व चेतावनी प्रणालियों के साथ, जलवायु से संबंधित नुकसान को कम करते हुए अनुकूलनता को बढ़ा रही हैं और जल, खाद्य और आजीविका सुरक्षा को मजबूत कर रही हैं।

उपरोक्त जलवायु पहलें विकसित भारत @2047 के विजन और वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने की प्रतिबद्धता के साथ रणनीतिक रूप से संरेखित हैं। समान और साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों और सम्बद्ध क्षमताओं (सीबीडीआर-आरसी) के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित, ये उपाय - दीर्घकालिक **निम्न** ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन विकास रणनीति (एलटी-एलईडीएस) में औपचारिक रूप से - एक साथ आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और औद्योगिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हैं। तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देकर और समुदायों और बुनियादी ढांचे की अनुकूलनता को मजबूत करके, ये पहलें जलवायु भेद्यता को कम करती हैं और विकास लाभों की रक्षा करती हैं, जिससे भारत का एक विकसित राष्ट्र में पदार्पण सुगम होता है।

****